पैन इंडिया कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता

आज़ादी का अमृत महोत्सव

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

पृष्ठभूमि

- दिशा योजना के तहत, कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का अब अखिल भारतीय स्तर पर विस्तार किया गया है।
- यह एक बहु-हितधारक, प्रगतिशील और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है जो कानूनी अधिकारों, अधिकारों और प्रासंगिक कानूनों पर महत्वपूर्ण जानकारी और जागरूकता के लिए कमजोर वर्गों को सक्षम करने के लिए नवीन विचारों, उपकरणों और सरलीकृत पद्धति को एकीकृत कर रहा है।

उद्देश्य

- कार्यक्षेत्र और वितरण के विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग
- विशेषज्ञ संस्थाओं के साथ साझेदारी करके विधिक साक्षरता को मुख्यधारा में लाना
- मौजूदा जमीनी स्तर/फ्रंटलाइन कार्यबल/स्वयंसेवकों का क्षमता निर्माण और उपयोग
- प्रभावशीलता को मापने के लिए संकेतक विकसित करना
- समवर्ती मूल्यांकन और आवधिक मूल्यांकन

भागीदार एजेंसियां

1. **भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली**
   राष्ट्रीय स्तर पर विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन।
2. **नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बंगलूरू, कर्नाटक**
   "डिजिटल कानूनी साक्षरता-प्रसार और आकलन"
3. **राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश**
   "डिजिटल विधिक साक्षरता-डिजाइन, विकास, प्रबंधन और परीक्षण –ई–न्यायगंगा"।
4. **राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू), नई दिल्ली**
   "उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र आयोजित करना" (अधिकारों का ज्ञान प्रगति की पहचान)।
5. **अरुणाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण (एपीएसएलएसए), इटानगर, अरुणाचल प्रदेश**
   "औपचारिक न्याय प्रदायगी प्रणाली पर गांव बुढा और गांव बुढ़ियों की क्षमता निर्माण द्वारा "पारंपरिक ग्राम न्याय परिषद प्रणाली और भारत के औपचारिक कानूनों की प्रथागत के बीच तालमेल"।
6. **सिक्किम राज्य महिला आयोग (एसएससीडब्ल्यू), गंगटोक, सिक्किम**
   "कर्मचारियोंए छात्रों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013, घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षण अधिनियम, 2005 मानव तस्करी रोध" पर प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम।
7. **मनोचिकित्सा विभाग, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा विज्ञान संस्थान (जेएनआईएमएस), इम्फाल ईस्ट, मणिपुर**
   "प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र आयोजित करके "बाल यौन शोषण के खिलाफ मीडियाकर्मियों, छात्रों, हितधारकों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण"।
8. **सेंटर फॉर कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स सोसाइटी (सीकोडेकॉन), जयपुर, राजस्थान**
   "राजस्थान के 5 आकांक्षी जिलों में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता को बढ़ावा देना"।
9. **शैडो एडवरटाइजिंग एण्ड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर, ओडिशा**
   ओडिशा राज्य में "अभिनव विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम"।
10. **यशवंतराव चव्हाण ग्राम विकास और प्रशासन लोक अकादमी (यशदा), पुणे, महाराष्ट्र**
    महाराष्ट्र की विन्हित ग्राम पंचायतों में "विधिवृत को बढ़ावा देना"।
11. **विधि अनुसंधान संस्थान (ईएलआरआई), गुवाहाटी, असम**
    "भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रथागत प्रथाओं का दस्तावेजीकरण"।
12. **बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), पटना, बिहार**
    ग्रामीण बिहार में विन्हित किए गए "विधि मित्रों को बढ़ावा देना"।
13. **अब्दुल नजीर साब राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मैसूर, कर्नाटक**
    (सैटकॉम) प्रौद्योगिकी के माध्यम से "पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के प्रतिनिधियों का विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम का प्रशिक्षण और संवेदीकरण"।
14. **मेघालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिलांग, मेघालय**
    सामुदायिक मध्यस्थता के माध्यम से न्याय तक पहुंच परियोजना।
15. **इंदिरा गाँधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली**
    इंदिरा गाँधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा अमलीकृत "पैरालीगल प्रैक्टिस मजबूतीकरण परियोजना"।
16. **डॉ॰ अम्बेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, पुडुचेरी**
    परियोजना "न्याया ओएलआई परियोजना-युवाओं के बीच कानूनी जागरूकता फैलाना"।

अंतर-मंत्रालयी अभिसरण

पंचायती राज
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

- 4 लघु फिल्में विकसित की गई हैं। इन लघु फिल्मों का पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भी प्रसार किया जा रहा है।

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY

- न्याय विभाग द्वारा प्रदान की गई कानूनी साक्षरता सामग्री शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए वेब पोर्टल दीक्षा (स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा) पर अपलोड की गई है।

कानूनी जानकारी के लिए सरलीकृत डिजिटल समाग्री

इत्ती सी हसी
https://youtu.be/Pu6-jembih0

जो मिल गया उसी को मुकदर समझ लिया
https://youtu.be/mHKUHL0npKI

लाखों तारे आसमान में
https://youtu.be/y55gzl7I8Qs

हम है रही प्यार के
https://youtu.be/HI0RoBETkwo

सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर वेबिनार

न्याय विभाग द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय-स्तर के सामाजिक कानूनी मुद्दों पर कानूनी जागरूकता वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया है। अब तक न्याय विभाग ने बीस वेबिनार आयोजित किए हैं। इन बीस राष्ट्रीय-स्तरीय वेबिनारों के माध्यम से न्याय विभाग 4.62 से अधिक प्रतिभागियों तक पहुँच चुका है।

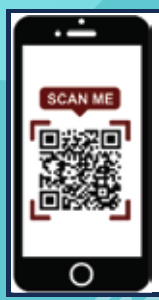

क्यू आर कोड के माध्यम से कानूनी जानकारी डिकोड करें

22 सितंबर, 2021 को 'घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम' 2005 पर आयोजित वेबिनार, 48,299+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

14 नवंबर, 2021 को 'बाल अधिकारों पर आयोजित वेबिनार' 17,644+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

26 नवंबर, 2021 को 'मौलिक कर्तव्य' विषय पर आयोजित वेबिनार, 24,082+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

7 जनवरी, 2022 को 'गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994' पर आयोजित वेबिनार, 15,080+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

18 फरवरी, 2022 को 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' पर आयोजित वेबिनार, 19,158+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

8 मार्च, 2022 को 'भारत में लैंगिक न्याय' पर आयोजित वेबिनार, 35,332+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

25 अप्रैल, 2022 को 'कानून के साथ संघर्ष में बच्चे' पर आयोजित वेबिनार, 20,207+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

27 मई, 2022 को 'देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे' पर आयोजित वेबिनार, 24,715+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

29 जून, 2022 को **'मानव तस्करी'** पर आयोजित वेबिनार 30,627+ प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

31 अगस्त, 2022 को **'वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार'** पर आयोजित वेबिनार, इसे 13,255+ लाभार्थियों से संपर्क किया गया ।

28 अक्टूबर, 2022 को **'भारत में साइबर अपराध'** पर आयोजित वेबिनार 30,442+ लाभार्थियों तक पहुंचा ।

25 नवंबर, 2022 को **'संवैधानिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों'** पर आयोजित वेबिनार 37,481+ लोगों तक पहुंचा ।

27 दिसंबर, 2022 को **'भारत में विकलांग व्यक्तियों'** के अधिकार पर आयोजित वेबिनार 16,612+ प्रतिभागियों तक पहुंचा ।

30 जनवरी, 2023 को **'भारत में विचाराधीन कैदियों'** के अधिकार पर आयोजित वेबिनार 17,960+ कार्यकर्ताओं तक पहुंचा ।

6 मार्च, 2023 को **'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और उनके अधिकारों का संरक्षण'** पर आयोजित वेबिनार 29,851+ प्रतिभागियों तक पहुंचा ।

28 मार्च, 2023 को **'उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण'** पर आयोजित वेबिनार 21,143+ प्रतिभागियों तक पहुंचा ।

12 जून, 2023 को **'भारत में बाल श्रम'** पर आयोजित वेबिनार 25,133+ प्रतिभागियों तक पहुंचा ।

18 जुलाई, 2023 को **'एसिड अटैक सर्वाइवर्स के पुनर्वास'** पर आयोजित वेबिनार 15,127+ प्रतिभागियों तक पहुंचा ।

29 सितम्बर, 2023 को **'श्रम कानून'** पर आयोजित वेबिनार 2153+ प्रतिभागियों तक पहुंचा ।

31 अक्टूबर, 2023 को **'बाल यौन शोषण'** पर आयोजित वेबिनार 33,318+ प्रतिभागियों तक पहुंचा ।

10 जुलाई, 2025 को **'साइबर अपराध और कानून: आधुनिक दुनिया में डिजिटल गिरफ्तारी को समझना'** पर आयोजित वेबिनार 5000+ प्रतिभागियों तक पहुंचा ।

28 अगस्त, 2025 को **'न्याय तक पहुँचरू एक संवैधानिक जनादेश और एक लोकतांत्रिक अनिवार्यता'** पर आयोजित वेबिनार 15,000+ प्रतिभागियों तक पहुंचा ।

25 सितंबर, 2025 को **'नए आपराधिक कानूनों के तहत बच्चों की सुरक्षा'** पर आयोजित वेबिनार 24,000+ प्रतिभागियों तक पहुंचा ।

हमारे उपयोगकर्ता इस प्लेटफॉर्म पर कानूनी ज्ञान की शक्ति को प्राप्त करने के लिए स्कैन करें

न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार

2024

सोशल मीडिया से डिजिटल कानूनी साक्षरता के लिए संपर्क करे **CEERA - NLSIU** का **QR** कोड स्कैन करें

समाचार में पैन इंडिया कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता